**Fourteenth Loksabha**

**Session : 7**
**Date : 07-03-2006**

**Participants : Rawat Prof. Rasa Singh**

an>

Title : Need to roll back the reduction of quota of wheat allotted to Rajasthan under A.P.L., B.P.L and other schemes.

**प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान केन्द्र सरकार ने राजस्थान के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयावन करने वाले लोगों से खिलवाड़ करते हुए बी.पी.एल. में कटोती करके तथा सामाजिक सुरक्षा एवं अन्नपूर्णा की विभिन्न योजनाओं में गेहूं के आबंटन में कमी कर दोहरी मार खाने को विवश कर दिया है। इस वित्तीय वर्ा में केन्द्र सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों को अप्रेल से जुलाई, 2005 तक 54318 मैट्रिक टन गेहूं तथा 600 मैट्रिक टन चावल आबंटित किया था, परन्तु अगस्त, 2005 से मार्च 2006 के लिए 41454 मैट्रिक टन गेहूं और 12658 मैट्रिक टन चावल आबंटित किया। इस तरह चावल की कुल मात्रा में वृद्धि कर गेहूं की कुल मात्रा में 12674 मैट्रिक टन की कमी की है। बी.पी.एल. योजना में गेहूं की कीमत 4.70 रुपए प्रति किलोग्राम है जबकि चावल की कीमत 6.00 रुपए प्रति किलोग्राम है। राजस्थान में चावल फूड हेबिट में नहीं होने एवं महंगा होने से गरीब परिवारों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। इस दोहरी मार से राजस्थान का गरीब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है।

महोदय, इसी तरह ए.पी.एल. योजना में अप्रेल से जुलाई 2005 तक 2 लाख 24 हजार 698 मैट्रिक टन के मुकाबले अगस्त, 2005 से मार्च 2006 के लिए 1 लाख 10 हजार 219 मैट्रिक टन आबंटन हुआ। इस तरह गेहूं की मात्रा में 63 हजार 479 मैट्रिक टन की कमी आई। इसी प्रकार कल्याणकारी संस्थाओं एवं छात्रा वासों के आबंटन में भी कटौती कर दी गई। परिणामस्वरूप चाहे बी.पी.एल. हो, चाहे ए.पी.एल., राजस्थान के नि वासियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में गेहूं एवं आटे के भाव बढ़ने के कारण ए. पी.एल. के गेहूं की मांग भी बढ़ गई है। इधर सार्वजनिक वितरण की दुकानों पर यह उपल्बध नहीं हो पा रहा है।

महोदय, इसलिए आम जनता महंगे भाव का गेहूं खरीदने को मजबूर है। इसी प्रकार अन्त्योदय एवं अन्नपूर्ण योजना में भी राजस्थान के आबंटन में भारी कटौती कर दी है जिसकी मार गरीबों को झेलनी पड़ रही है। राजस्थान सरकार केन्द्र सरकार को दो बार पत्र लिखकर बी.पी.एल. परिवारों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्ति कर चुकी है, परन्तु फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान को आबंटित ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. तथा अन्य योजनाओं में आबंटित गेहूं के कोटे की भारी कटौती को तुरन्त प्रभाव से वापस लिया जाए तथा चावल के स्था पर गेहूं अधिक एवं पूरी मात्रा में देने की अविलम्ब व्य वस्था की जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Santasri Chatterjee – Not present.